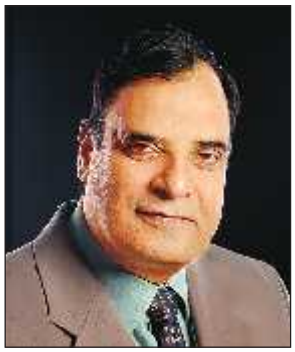

आलोक मेहता

पेट पालने के लिए जरूरी है सड़क

श्री राहुल गांधीजी,

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सभाओं में जयकार और दिल्ली में उदासीन पलायन के अलग-अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। विधानसभाओं के चुनाव परिणामों से आप, कांग्रेस पार्टी और प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी संभवतः कुछ सबक लेने का प्रयास करेगी। लोकतंत्र में जीत-हार से अधिक महत्वपूर्ण है- जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास और सुनहरे भविष्य का विश्वास। फिर भी ऐसा कैसे हुआ कि कुछ जन सभाओं में आपने बहुत जोशीले स्वर में कहा- 'चमचमाती सड़कों से पेट नहीं भर सकता। गरीब लोगों की गरीबी मिटाना अधिक जरूरी है। उन्हें खाद्यान्न देने का इंतजाम हमारी कांग्रेस सरकार कर रही है। हम किसी बच्चे को भूख से नहीं मरने देंगे।' गरीब और भुखमरी से निजात का वायदा अच्छा लग सकता है, लेकिन आपने अथवा आपके अति योग्य सलाहकारों ने बंद कमरों की मंत्रणाओं के दौरान क्या किसी जमीनी कार्यकर्ता या गांव के गरीब आदमी से इस मुद्दे की असलियत पता लगवाने की कोशिश की? अन्यथा एक जगह गलत बोलने पर अगली किसी सभा में मुद्दे को दुरुस्त किया जा सकता था। यही नहीं कांग्रेस 'वार रूम' में बैठे आपके पसंदीदा मंत्री सी.पी. जोशी भी यह बताना कैसे भूल गए कि राजीव गांधी के कार्यकाल से लेकर मनमोहन सरकार के लगभग साढ़े नौ वर्ष के सत्ता काल में राष्ट्रीय स्तर पर 42,632000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछाने के लिए व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित होता रहा। पिछले कुछ वर्षों में आपकी ही सरकार ने करीब 4200 अरब रुपये सड़क-निर्माण पर खर्च किए। आपकी सरकार ने बड़े शहरों को जोड़ने के लिए चार या छह लेन की 19200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया और उद्योग-व्यापार की सुविधाएं बढ़ीं। आपकी सरकार और पार्टी अपनी सफलताओं में जोर-शोर से इस बात को प्रसारित करती है। यही नहीं दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र में कांग्रेस की राज्य सरकारें सड़कों और पुलों को विकास का सबसे बड़ा प्रमाण बताती हैं।

> आप अकेले नहीं हैं। अत्याधुनिक टेक्नालॉजी ने कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों में जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी बढ़ा दी है। फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल से वह बातें आपके दिमाग में नहीं उतर सकतीं, जो हर तीसरे चौथे दिन आपके घर-अहाते में पहुंचने वाले कार्यकर्ता या साधारण आदमी के मुंह से पहुंच सकती हैं। उसके दर्द की अनुभूति मशीन से कतई नहीं हो सकेगी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी की सफलता का राज यही था कि उनका जीवंत संपर्क अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक रहता था।

निश्चित रूप से छोटे कस्बों-गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इस दृष्टि से यदि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकारें सड़कें बनाने का दावा कर भी रही हों, तो उसे आप 'निरर्थक', 'अनुपयोगी' श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? आप यह कैसे भूल गए कि 10 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पराजय का कारण भाजपा का सड़क, पानी, बिजली की सुविधा सुनिश्चित कराने का था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नवंबर 2013 के विधान सभा चुनाव में भी क्षेत्रीय टी.वी. न्यूज चैनलों से जनता के बीच पहुंचने वाले कार्यक्रमों में सामान्य लोग सड़कों की खराब हालत की शिकायतें सबसे ज्यादा कर रहे थे। यदि आपके सहयोगियों ने सही जमीनी रिपोर्ट दी होती तो, आपको सड़क की अनुपयोगिता के बजाय गड़बड़ियों का उल्लेख करना उचित लगता। दिक्कत यह है कि आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदारों ने भी 'रोड शो' भले ही किये हों, ग्वालियर से भोपाल तक सामान्य मोटरगाड़ी में सड़क से यात्रा नहीं की होगी। नवंबर के प्रारंभ में दो वरिष्ठ पत्रकारों ने सड़क मार्ग से दिल्ली से भोपाल तक की यात्रा की। उनका अनुभव तो बेहद खराब था, क्योंकि सड़कों की हालत खस्ता थी। भाजपा के नेता शायद उन्हें पूर्वाग्रही करार दें, लेकिन छोटे कस्बों और गांवों के लोग टी.वी. कैमरों के सामने सड़कों की जर्जर हालत दिखाकर गुस्सा व्यक्त करते रहे।

उनसे अधिक आपत्ति मुझे आपकी इस बात पर है कि 'सड़कों से पेट नहीं भरता।' राहुलजी, यदि गांव-कस्बे के बीच सड़क नहीं होगी, तो आपकी 'महत्वाकांक्षी खाद्यान्न सुरक्षा योजना' के तहत अनाज गरीबों तक कैसे पहुंचेगा? आप या आपके प्रिय युवा नेतागण कभी ऐसे गांव तक जाने की कोशिश करें, जहां बैलगाड़ी, घोड़े से या पैदल ही पहुंचा जा सकता हो। हेलीकॉप्टर का प्रयोग कृपया न करें। फिर वहां के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं से पूछने का प्रयास करें कि सड़क के बिना उन्हें कितनी कठिनाइयां हैं। इसी तरह किसी युवा शिक्षक और डॉक्टर से पता लगाएं कि वह सड़क मार्ग से 20-25 किलोमीटर दूर के गांव में तैनाती के लिए क्या तैयार रहेगा? मजबूरी में वह हां कर लेगा, तो वहां लगातार कितने दिन रह सकेगा? न्यूनतम शिक्षा और चिकित्सा सुविधा के लिए सड़क क्या बहुत जरूरी नहीं है? गांव में सुविधा न होने से बच्चे भी यदि पास के गांव-कस्बे तक पहुंचना चाहेंगे, तो बिना सड़क के कैसे जायंगे? गांव में थोड़ा-बहुत अनाज, दूध, सब्जी, आम-अमरूद मिल सकता है, लेकिन नमक, आटे, दाल, साबुन, कुंए के पानी को साफ करने के लिए दवाई का इंतजाम करने के लिए पास की देहात, कस्बे तक जाना क्या जरूरी नहीं होगा? पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों की वनोपज या फल-सब्जी को कस्बों-शहरों तक पहुंचाने के लिए क्या सड़कों की जरूरत नहीं होगी? गरीब परिवार पेट पालने के लिए घर-गांव से बाहर जाकर देर शाम घर लौटने की इच्छा क्यों नहीं रखेगा? आपके ज्ञानी सलाहकार कैसे भूल गए हैं कि हड़प्पा-मोहनजोदड़ों से लेकर शेरशाह सूरी के मुगलकाल में भी सड़कों के निर्माण ने इतिहास और संस्कृति को सुरक्षित बनाया था।

आप अकेले नहीं हैं। अत्याधुनिक टेक्नालॉजी ने कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों में जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी बढ़ा दी है। फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल से वह बातें आपके दिमाग में नहीं उतर सकतीं, जो हर तीसरे चौथे दिन आपके घर-अहाते में पहुंचने वाले कार्यकर्ता या साधारण आदमी के मुंह से पहुंच सकती हैं। उसके दर्द की अनुभूति मशीन से कतई नहीं हो सकेगी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी की सफलता का राज यही था कि उनका जीवंत संपर्क अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक रहता था। इसीलिए उनके सत्ताकाल में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। लैपटाप की बजाय स्कूलों के कच्चे-पक्के भवन, टाटपट्टी, टेबल-कुर्सी, पुस्तकालयों के लिए आलमारी ज्यादा जरूरी हैं। महानगरों में पांच सितारा निजी अस्पताल भले ही बन जाएं, गांवों में न्यूनतम दवाई, मरहम पट्टी और थोड़े समझदार डॉक्टरों की अधिक जरूरत है। कम से कम लोक सभा चुनाव का एजेंडा तय करते समय 'वार रूम' में ऐसे मुद्दों पर भी थोड़ा समय लगाने का कष्ट करें।

alokmehta7@hotmail.com